

अस्सलामो अल्यकुम !

में अपने सभी भाइयों का तहेदिल से शुक्रगुज़ार हूँ, के आप लोगों ने वक्त की ज़रूरत को, और वक्त की आवाज़ को समझा, और इस ठण्ड में, अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ आये. और में आपसे वादा करता हूँ, की यहाँ आना आपका जाए नहीं जायेगा.

आज हमने, अपने मकसद की पहली सीडी पर कदम रखा है, और में वादा करता हूँ की, इंशाल्लाह, मंजिल भी एक दिन कदमों में होगी. और, मुझे खुशी है, के में आज आप लोगों के बीच हूँ, क्युकी ये प्रोटेस्ट, हिंदुस्तान की तारीख में, आज़ादी के बाद सबसे बरी क्रांति का आगाज़ होगा. इंशाल्लाह.

जब हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरु ने, अपनी तकरीर में कहा था, की "हम सभी, चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक रखते हो, हिंदुस्तान के बराबर के बचे हैं, और सबका बराबर हक, विशेषाधिकार और ज़िम्मेदारी हैं. हम सांप्रदायिकता और संकीर्ण मानसिकता को बढ़ावा नहीं दे सकते, क्युकी कोई भी देश महान नहीं बन सकता, जब तक उसके लोग अपनी सोच और काम में संकीर्ण हो."

मगर सेकुलर कानून, और तमाम संवैधानिक अधिकारों के होने के बावजूद, मुसलमानों को समय-समय पर, मुसलमान होने की कीमत चुकानी पड़ती है, जिसकी तरफ शायद ही किसी का ध्यान जाता है. खास तौर पर वे नौकरशाही, और सुरक्षा एजेंसियों की फिरकावाराणा सोच का सबसे बड़ा शिकार हैं. बिना गुनाह के उन्हें, अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ती है.

मुसलमानों पर बद एतमादी, और उन्हें शक की निगाह से देखा जाना, एक बड़ी वजह रही, जिसके चलते वे शुरुआत से ही तरक्की की दौड़ में पिछड़ते चले गए. दरअसल मुसलमानों को एक मंसूबे के तहत, आला तालीम और सरकारी नौकरियों से दूर रखा गया। सेना के सेलेक्शन में आज भी ऐसी मानसिकताएं काम कर रही हैं, जो सेना में मुसलमानों के चुने जाने के खिलाफ हैं. अलबत्ता, संविधान के तहत समानता का हक उसे भी हासिल है.

मुस्लिम समुदाय शिक्षा स्वास्थ्य, आर्थिक सुरक्षा और सार्वजनिक क्षेत्र आदि में बहुसंख्यक समाज से काफी पीछे है. नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च और अमेरिका के मैरीलैंड विश्वविद्यालय द्वारा कराए गए इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट का हाल में आया सर्वे देश में मुसलमानों के बदतरिनी हालात को बयां करता है. बावजूद इसके मुल्क के हुक्मरानों को कहीं भी भेदभाव नज़र नहीं आता. 1980 में गोपाल सिंह कमेटी और बाद में सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्टों में मुसलमानों की तस्वीर बहुत हद तक नज़र आई है. मुसलमानों के समग्र विकास के लिए सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सरकार से कई सिफारिशें की थीं. सबसे अहम सिफारिश थी, सरकारी नौकरियों में मुस्लिमों के प्रति होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए समान

अवसर आयोग की स्थापना, लेकिन समान अवसर आयोग अभी तक हकीकत नहीं बन पाया, जबकि सत्तारूढ़ कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणापत्र में समान अवसर आयोग गठित करने का वादा किया था।

मुस्लिमों की आय का मुख्य ज़रिया खुद का रोज़गार है। सच्चा कमेटी का आकलन था कि मुसलमानों को वित्तीय संस्थाओं से दूसरों की अपेक्षा कम कर्ज़ मिलता है। उन्हें कर्ज़ देने में आनाकानी की जाती है। हर जगह यह हालत होने के बावजूद कहीं भी इसकी निगरानी नहीं होती। लिहाज़ा सरकार ने इस दिशा में सुधार करने के लिए मुस्लिम नौजवानों को स्वरोज़गार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कर्ज़ की सहूलियत बढ़ाने, आगामी 3 साल में कर्ज़ मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 15 फीसदी तक ले जाने और इसकी निगरानी करने का वादा किया था, लेकिन हालात आज भी बिल्कुल नहीं बदले हैं। इस मामले में खुद सरकारी आंकड़े कुछ और कहानी बयां करते हैं। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2009-10 में गुजरात में सरकारी बैंकों ने यहां अल्पसंख्यकों को 5,341 करोड़ रुपये देने का लक्ष्य रखा था, वहीं बांटा सिर्फ 1860.81 करोड़ रुपये यानी महज़ 34.84 फीसदी। मुसलमानों को कर्ज़ देने के मामले में सबसे हैरतअंगेज़ बात यह है कि चाहे गुजरात में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार हो या फिर दिल्ली में शीला दीक्षित की कांग्रेस सरकार, दोनों का मुसलमानों को कर्ज़ देने के मामले में एक जैसा रवैया है। दिल्ली में यह लक्ष्य 5,982 करोड़ रुपये का था, लेकिन बांटे गए महज़ 3,165 करोड़ रुपये। यानी लक्ष्य का महज़ 52.97 फीसदी। कमोबेश यही हाल कांग्रेस शासित अन्य राज्यों महाराष्ट्र एवं राजस्थान का रहा, जहां तय लक्ष्य का 50 और 58.51 फीसदी ही कर्ज़ बांटा गया।

इस सब से ये बात साफ़ ज़ाहिर है और सब के सामने है के आज की सरकार धर्म निरपेक्ष नहीं, सिर्फ़ धर्म निरपेक्षता का नकाब पहने है। और यही वो वजह है, जिसके चलते मुसलमान चाह कर भी मुख्य धारा में नहीं आ पा रहे हैं।

मगर शायद ये लोग ये भोल जाते हैं के कोई भी देश तरक्की की बुलंदी पे नहीं पहुच सकता जब तक उसकी सेकंड लास्टेस्ट आबादी तालीमी, आर्थिक और सामाजिक तोर पर बे तरफ कर दी जाये। मुसलमानों के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक उत्थान से न सिर्फ़ इस समुदाय की हालत सुधरेगी, बल्कि देश का भी समुचित विकास होगा। उपेक्षित तबकों की न्यायोचित आकांक्षाओं-मांगों की अनदेखी भला कब तक की जा सकती है। सामाजिक न्याय सभी जगह ज़रूरी है। न्याय होगा तो मुसलमानों के विकास में भी झलकेगा। ज़ाहिर है, मुस्लिम समुदाय का विकास देश के विकास से अलग नहीं है।

यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं की अरे मुसलमानों तुम कब मुतमईन होओगे? हम जब तक मुतमईन नहीं हो सकते जब तक अकलियत यहाँ हिंदुस्तान में पुलिस के ना बताये जा सकने वाले जुल्म के खोफ और सियासी साजिश का शिकार है। हम जब तक मुतमईन नहीं हो सकते जब तक अकलियतों की अजमत हिंदुस्तान में महफूज़ नहीं। हाँ, हम मुतमईन नहीं हैं, और हम मुतमईन हो भी नहीं सकते, जब तक हिंदुस्तान में इन्साफ और सच्चाई साफ पानी की तरह ना बहने लगे।

बंटवारे के बाद इस मुल्क में मुसलमान ही है जो सबसे ज़्यादा टोटे और ख़सारे में रहा। इस क्रौम का सभी सियासी जमातों ने खून चूसा और मौजूदा दौर में भी चूसा जा रहा है। मगर ये क्रौम है जिसे अपने छले जाने तक का अहसास नहीं। इस की बदकिस्मती ये है कि इस के साथ हमदर्दी तो बहुतेरे सियासी रहनुमाओं ने दिखाई मगर किसी न किसी गर्ज से। देशभर में आज हर क्रौम के नेताओं की भरमार है। दलित हो, पिछड़ा हो, पंडित, बनिया, पंजाबी, आदिवासी और न जाने कितनी क्रौमें, गिनना भी आसान नहीं। नेता सबके हैं। मगर नेताविहीन अगर कोई क्रौम है तो सिर्फ मुसलमान। देश की तमाम सियासी जमातों ने इस क्रौम को पिछलग्गू बना लिया पर साझेदार नहीं। इनके वोट का इस्तेमाल तो सब ने किया मगर समस्याओं को समाधान नहीं। मुसलमानों के बूते पर कांग्रेस ने पचास साल से भी ज़्यादा राज किया। लालू प्रसाद यादव बीस साल तक मुसलमानों के दम पर सत्ता का सुख भोगते रहे। न जाने कितने नेता इसी वोट बैंक के आधार पर सत्ता की मलाई मारते रहे। लेकिन मैं एक सवाल करता हूं, देश के किसी भी बड़े सियासी दल का मुखिया कोई मुसलमान क्यों नहीं है?

जबकि मुसलमानों के वोटों पर ही उन्होंने सत्ता का सुख भोगा है। ऐसा ही हाल दूसरे नेताओं का भी है। मुसलमान को भीख का टुकड़ा तो हर दर से मिला मगर भागीदारी कहीं से नहीं। ग़ौर करने वाली बात है कि हिंदुस्तान की किसी पार्टी में कोई मुसलमान नेता इस क्रद और कुव्वत का है जो सीना चौड़ा कर मुसलमानों का हक़ मांगने की जुरत रखता हो। या फिर अपनी संख्या के आधार पर लोकसभा और राज्य सभा में भागीदारी मांग सके। सच्चाई ये है कि वो अपनी आबादी के आधार पर अपनी पार्टी से मुसलमानों को टिकट तक नहीं दिलवा सकता। मंसूबे साफ़ ज़ाहिर हैं। समझने वाले समझ भी रहे होंगे। कोई हिंदू नेता, हिंदू कट्टरवादी नेता या संगठन को गाली दे दे तो वो मुसलमानों का मसीहा बन जाता है।

अरे हमें किसी की बुराई की पोटली नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ़ हमारा हक़ चाहिए, वोह भी भाईचारे के साथ।

कांग्रेस अपने आपको धर्मनिरपेक्ष पार्टी बताती है। हां इतना ज़रूर है कि इस पार्टी ने धर्मरपेक्षता का मुखौटा ज़रूर पहन रखा है। इस मुल्क में मुसलमानों की मुसीबतों और उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कांग्रेस ने ढिंढोरा तो ख़ूब पीटा। मगर क्या उसे दूर करने के लिए कोई अमली जामा पहनाया? सच्चा कमेटी की रिपोर्ट ने सही मायने में कांग्रेस की बर्इमान नीयत की ही पोल खोली है। ये सवाल मैं आम मुसलमान से पूछ रहा हूं। क्या ऐसा हुआ है? नई सरकारें आती हैं, नए नए आयोग बनते हैं। और नए नए वायदों के कागज़ी मसौदे तैयार होते हैं। लेकिन वो हमेशा दफ्तरों की फाईलों में धूल चाटते चाटते दम तोड़ देते हैं। ईमानदारी बरती गई होती तो 64 साल की आज़ादी में मुसलमानों का यही हाल हुआ होता जो आज है?

इस मुल्क में हुए दंगों ने न जाने कितने मज़लूम, बेबस, बेगुनाह और लाचार मुसलमानों की जान ले ली। न जाने कितने आयोग बैठे। लेकिन कोई आयोग किसी दोषी को सज़ा की दहलीज़ तक नहीं पहुंचा पाया। क्रातिल भी वही मुंसिफ भी वही। भला इंसान मिलता भी तो कैसे।

खासतौर से कांग्रेस की ये पोलिसी रही कि मुसलमानों को भय यानी खौफ और दहशत में रखा जाए। उनको जनसंघ जैसे हिंदू कट्टरवादी संगठनों का खौफ दिखाकर, कांग्रेस की ओर आकर्षित करने का काम किया गया। इसी साज़िश के तहत पहले मुसलमानों को पिटवाया और फिर पुचकारा। यही वजह रही कि मुसलमान कांग्रेस का वोट बैंक बना रहा।

एक लंबा समय ऐसा गुजरा है जब मुसलमान ने सरकार से न रोटी मांगी न रोज़गार। मांगी तो सिर्फ अपने जान माल की हिफाज़त। मैं कहता हूँ की कोई भी दंगा हिन्दू मुस्लिम नहीं होता, होता है तो सिर्फ मुस्लिम बनाम सियासत.

बात दिल्ली के उसी बटला हाउस ऐंकाउंटर की जिस पर जम कर राजनीति की रोटियां सेंकी गई। सियासत सब ने की। कांग्रेस हो, भाजपा, सपा, बसपा, आरजेडी समेत और कई दलों ने इसी मुद्दे पर अपनी-अपनी दुकानदारी काफी दिनों तक चलाई। दुकान नेताओं की ही नहीं चली बल्कि मीडिया वालों को भी अपनी दुकान चलाने का मौक़ा मिला। ज़रा उस दौरान के तमाम न्यूज़ चैनलों की क्लिपिंग उठाकर देख लीजिए। हर कोई मीडिया वाला खुद ही जांच ऐजेंसी और खुद ही जज बनकर फैसला सुना रहा था। सबकी कहानी जुदा थी। न्यूज़ चैनलों का किसी एक बात पर इत्तिफ़ाक़ नहीं था। सबसे पहले मैंने आज तक न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर शम्स ताहिर ख़ान की रिपोर्ट देखी जिसमें उसने साफ़-साफ़ इसे फ़र्ज़ी ऐंकाउंटर करार दिया। फिर इसी तरह की खबरें कुछ दूसरे न्यूज़ चैनलों पर भी आने लगीं। राजनैतिक दल और मीडिया भी दो टुकड़ों में बंट गए। कुछ असली तो कुछ इसे फ़र्ज़ी ऐंकाउंटर साबित करने में जुटे थे। लोगों के सामने सच्चाई आज तक नहीं आई। और न आएगी। सरकार तब भी कांग्रेस की थी और आज भी।

दूसरों से क्या शिकवा करें, हम लोगों को अपने वोट की ताक़त का अहसास ही नहीं। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ देश की कोई सियासी जमात बिना मुसलमानों के इस मुल्क की सत्ता हासिल नहीं कर सकती। लेकिन मुसलमानों को इसका अहसास नहीं। सब खून निचोड़ने पर लगे हैं और हम निचुड़ने को सदा तैयार। दरअसल हमारे अंदर भीख के टुकड़ों पर पलने की आदत बन गई हैं। चंद मुसलमानों को मंत्री या किसी आयोग का चैयरमैन बना दिया जाए तो सारी क्रौम गदगद हो जाती हैं। तमाम क्रौमें सत्ता में अपनी-अपनी भागीदारी पा चुकी हैं। एक हम ही हैं जो साझेदारी से दूर हैं। मुल्क में हमारी गिनती 20 फ़ीसदी कही जाती है। क्या किसी मुसलमान ने आवाज़ उठाई कि लोकसभा और राज्यसभा में हमारी तादाद आबादी के लिहाज़ से होनी चाहिए।

मैं आज आप से कहना चाहता हूँ की जो हालात आज हमारे सामने हैं वो कोई प्रोपगंडा नहीं है, यहाँ बहुत सी समस्याएं जिनमे से कुछ बहुत संगीन हैं आज हमारे सामने हकीकत मैं खरी हैं, इन समस्याओं का हल हम आसानी से या बहुत जल्द नहीं निकाल सकते. लेकिन ये बात याद रखो की हम इन से उपर निकल कर ज़रूर आएंगे अगर हम ने कोशिश की तब.

आज के दिन हम यहाँ सिर्फ इस लिए इकहत्त हुए हैं क्युकी हमने डर को छोड़कर उम्मीद को पकड़ा है, क्युकी हमने टकराव और मतभेद को छोड़कर भाईचारे को अपनाया है.

हमारे सामने नयी नयी चुनोतिया आ सकती हैं, जिनके लिए हमे नयी नयी योजनाओ की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन जिनके उपर हमारी कामयाबी टिकी है वो है -- कड़ी मेहनत और ईमानदारी, साहस और

रवादारी, इन्साफ और वफादारी –जो की एक सच्चाई है. आप तारीख उठा कर देख लें की यही वो चीजें हैं जिससे हमने हर फिल्ड में कामयाबी हासिल की.

लेकिन, हम अकेले नहीं चल सकते. और जब हम चलें, हम कसम खा लें की अब हम आगे ही बढ़ेंगे, और हम अब वापस नहीं मुड़ेगे.

हिंदुस्तान के इतिहास के पन्नों को ज़रा पलटये। इस मुल्क में अगर सबसे ज़्यादा शोषण किसी का हुआ है तो वो दलित बिरादरी। ये तबक़ा सदियों से दबा कुचला था। दाद देनी पड़ेगी डाक्टर भीमराव अम्बेडकर को। जिस शख्स ने अपनी क्रौम के दर्द का अहसास किया। और दलितों को एक दिशा दिखाने का काम किया। क़ाबिले तारीफ़ काशीराम भी हैं। जिन्होंने दलितों के विकास का जो बीज बोया उसका पौधा अब फल देने लगा है। दलितों की हालत आज मुसलमानों से कहीं बेहतर है। आज वो भीख के टुकड़ों पर नहीं पलते। अपने वोट के दम पर सत्ता के भागीदार बनते हैं। आज उनकी भागीदारी हर जगह नज़र आती है। प्रशासन, न्याय पालिका या फिर कार्य पालिका। मगर मुसलमान हर जगह से नदारद है। उसकी हिस्सेदारी कहीं नज़र नहीं आती। ये हालात अचानक नहीं बदले। इसके लिए दलितों ने अपनी बिरादरी के लोगों को वोट की ताक़त का एहसास कराया। और जब वोट की ताक़त उनकी समझ में आई तो सत्ता का सुख मिलने में कोई देर नहीं लगी। एक अनपढ़ क्रौम जागरूक हो गई। आज वो संगठित हैं। बिना शर्त वो किसी को समर्थन नहीं देते। पहले अपने मतलब की बात करते हैं बाद में समर्थन की। लेकिन एक मुसलमान है। जो जज़्बात में आकर बिना किसी शर्त, बिना सोचे समझे किसी को भी अपना वोट दे देता है। ज़रा कोई उसकी शान में चार शब्द कह दे, बस उसी पर अपना सबकुछ न्यौछावर कर देता है।

सरकार में दूसरे दलों की साझेदारी तो आप लोग देख ही रहे होंगे। सरकार चलाने वाले दल की मजाल नहीं कि वो अपने यहयोगी दल को नाराज़ कर दे। भले ही सहयोगी दल के पास 10-20 सांसद ही क्यों न हों। इसे कहते हैं साझेदारी।

हर चुनाव के बाद सत्ता की मंडी लगती रही। और हर दल का मुखिया जिसके पास भले ही दो चार सांसद थे वो भी सौदेबाज़ी के नपे-तुले अंदाज़ में नज़र आया। हर चुनाव के बाद लगने वाली सत्ता की मंडी में सौदागरों ने जमकर अपने हुनर दिखाए। सरकार को समर्थन अपनी शर्तों के आधार पर दिया। और यही लोग सत्ता के भागीदार बने। लेकिन अफसोस, मुसलमानों के वोटों का सौदा करने वाले कोई और ही थे। अब तक सत्ता के लिए लगने वाली मंडी में जितने सौदागरों की भीड़ का जमावड़ा जमा हुआ। उनमें कोई मुस्लिम सौदागर नहीं था। कितने शर्म की बात है। वोट हमारा और सौदा करे कोई और। अफसोस की बात तो यह भी है कि जिन नेताओं, जैसे रामविलास पासवान मुसलमानों के दम पर नेता बने और सौदा कर भाजपा में मंत्री बन गए। लालू, मुलायम समेत और बहुत सारे नेता हैं। जो मुस्लिम वोटों के बूते पर सत्ता के बाज़ीगर बनकर उभरे। लेकिन सौदा करते वक्त किसी भी नेता ने मुसलमानों से सलाह मशवरा तक करना गवारा नहीं किया। दरअसल इन लोगों ने भी कांग्रेस की ही तर्ज़ पर मुसलमान को गुलाम से आगे की हैसियत नहीं दी।

मैं नहीं आप भी बहुत सारे मुस्लिम क्रद्दावर नेताओं को जानते होंगे। सारे नाम लिखें तो फेहरिस्त बहुत लंबी हो जाएगी। सीके जाफर शरीफ, अब्दुल रहमान अंतुले, आरिफ मोहम्मद खान समेत और बहुत से नेता कांग्रेस में कभी क्रद्दावर की हैसियत रखते थे। मगर अब कहां गुम हो गए, पता नहीं। कांग्रेस के अलावा और तमाम दलों के नेताओं का भी यही हाल हुआ है। जब तक चाहा मुस्लिम नेता का इस्तेमाल किया और जब चाहा बाहर का रास्ता दिखा दिया। शहाबुद्दीन, तसलीमुद्दीन जैसे नेता लालू की पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं। लेकिन ये लोग आज कहां नदारद हो गए। कहानी लगभग सबकी एक ही जैसी है। दरअसल खुद की ज़मीन किसी के पास नहीं थी। तमाम मुस्लिम नेता मुसलमानों में अपनी पेंठ बनाने के बजाए पार्टियों में पकड़ मज़बूत बनाने में जुटे रहे। किसी ने अपने संगठन पर काम नहीं किया। सत्ता के सुख के लिए जिनके कंधों पर रखकर बंदूक चलाई थी। उन्होंने अपना कंधा जैसे ही खींचा सड़क पर आने में देर नहीं लगी। ज़मीन नहीं थी तो पार्टियों को भी इन्हें बाहर का रास्ता दिखाने में कोई दुशवारी नहीं हुई। चूंकि एक को निकाला तो सौ मुसलमान पार्टी की चापलूसी के लिए क्रतार में खड़े नज़र आए। जिनकी कभी तूती बोलती थी, बहुत सारे नेता गुमनाम हो गए।

बहुत से नेता तक़रीरों में क्रौम के लिए अपना सारा खून बहा देने तक का दावा भरते थे। मगर देश में मुसलमानों के साथ इतना कुछ हो जाने के बाद भी मैंने किसी मुस्लिम नेता के खून का एक क्रतरा तक बहते नहीं देखा। सत्ता में शामिल होते ही इन तमाम नेताओं की जुबान पर ताला लग जाता है। तक़रीरें तो 64 सालों से होती आ रही हैं। नतीजा कुछ नहीं निकला। ज़रूरत तो साझेदारी के लिए ज़मीन तैयार करने की है। और ज़मीन ऐसे ही तैयार नहीं होगी। सड़कों पर पसीना बहाना होगा। मुझे लगता है इस तहरीक को चलाने के लिए बंदूक में चले हुए कारतूसों की ज़रूरत नहीं। जिन्हें परखा जा चुका हो उन्हें दोबारा परखने की ज़रूरत नहीं।

नेता की ताक़त उसका वोट होता है। और वोट हमारे और तुम्हारे पास है। अब हमें नेताओं की नीयत को परखना होगा। ये लोग मदारी की तरह डुगडुगी बजाकर मजमा जोड़ना जानते हैं। यदि मुसलमानों को सत्ता में भागीदारी चाहिए तो नेताओं की डुग-डुगी की पहचान करनी होगी। खुद अपने भले और बुरे की परख करनी होगी। अब वोट का इस्तेमाल आंखें खोल कर करना पड़ेगा।

आज जबकि देश की आबादी का लगभग 20 फीसदी हिस्सा मुस्लिम आबादी का है। इस लिहाज से देश के हर सोबे में इसी अनुपात से मुसलमानों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। देश की विधान सभाओं और लोकसभा में आबादी के अनुपात में बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। सरकारी नौकरियों और प्रशासनिक अमले में भी आबादी के अनुपात में भागेदारी होनी चाहिए। लेकिन जो नहीं हैं। और ये नौबत हमारे संगठित हुए बिना नहीं आ सकती।

हमने अपनी बुनियादी मुश्किलात को दरकिनार कर दिया है। और वक्त गुजर रहा है बेवजह की बातों में। हमें ज़रूरत है सियासी तंजीम पर काम करने की। हमें ज़रूरत है एक इंकलाब की। हमको भागीदारी के लिए देश में एक आंदोलन खड़ा करना होगा। उसके लिए तहरीक चलाएं, मुसलमानों को जगाने का काम करें। इस पर हमारा वक्त खर्च होगा तो

हो सकता है कि भागीदारी के पेड़ की जड़े मज़बूत होने लगें। ये भी मुमकिन है कि पेड़, फल फूल गया तो फल हम खाएंगे। और तैयार होने में देर लगी तो हमारी नस्लों को फल ज़रूर मिल जाएगा।

अज़ीज़ो सितारे टूट गए तो क्या हुआ सूरज तो चमक रहा है | उससे किरणें मांग लो और उन अँधेरी राहों में बिछा दो जहाँ उजाले की सख्त ज़रूरत है | आओ वादा करें कि ये मुल्क हमारा है | हम इसके लिए हैं, और इस की तकदीर के बुनियादी फैसले हमारी आवाज़ के बगैर अधूरे ही रहेंगे.

ये वादा लिया था हमसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, मगर आज भी हम उसी चोराहे पर खड़े हैं जहाँ उस वक़्त खड़े थे.

अब वक़्त आ गया है के जम्हूरियत के वादों को सच्चाई में बदले. अब वक़्त आ गया है के अँधेरे से निकलकर रौशनी की तरफ आयें. अब वक़्त आ गया है के सामाजिक नाइंसाफी से निकलकर आपसी भाईचारे की तरफ हिंदुस्तान को लेजाएं. अब वक़्त आ गया है के अल्लाह के सभी बन्दों के लिए इंसाफ को कायम करे.

आप अपनी आने वाली नस्लों को कोन सा हिंदुस्तान देना चाहते हो? ऐसा हिंदुस्तान जो हमें मिला,

या ऐसा हिंदुस्तान जहाँ पर वो इंसाफ और हक के साथ साँस ले सकें?

मुसलमानों को अपनी वोट की ताकत का अहसास कराकर उनमें इतनी समझ पैदा की जाए, कि जहमुरियत में सत्ता पर काबिज होने के लिए अपने आपको संगठित करना निहायत जरूरी है। यदि कोई समुदाय अपने आपको इस काबिल या कफिल बना लेता है कि वो वोट की ताकत पर खुद सत्ता हासिल कर ले। यदि ऐसा नहीं कर पाता तो दूसरे को सत्ता में लाने और रोकने का काम कर सकता है। तो यह लाज़ीम हो जाता है कि ऐसे सियासी दल खुद ब खुद उसकी अहमियत को समझकर उसकी हिस्सेदारी को तसलीम किए बैगर नहीं रह सकते। ऐसी स्थिति में मुसलमानों का दोनों परिस्थितियों में फायदा ही फायदा है। ऐसे में मुसलमानों को हर सोबे में विकास होना लाज़मी है। इसलिए मौजूदा परिस्थितियों के मद्दे-नज़र मुसलमानों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की लिए दीनी और सियासी रहनुमाओं को मिलकर और आपसी सुझबुझ के साथ काम करना चाहिए। ताकि मुसलमानों की आबादी को वोट की ताकत में तबदील किया जा सके। ऐसा होने पर आज जो मुसलमान अपने आपको अपने ही देश बेगाना समझ रहा है। उसको यह समझने में देर नहीं लगेगी कि वो अपने देश में बेगाना नहीं बल्कि असली हिस्सेदार है।

मैंने समझाने की कोशिश की है कि अपने आपको संगठित कर सत्ता में भागीदारी हासिल करो। सत्ता में भागेदारी मिली तो मसाइल सारे अपने आप हल हो जाएंगे। अपना हक हासिल करो। खदरधारियों की कैद से खुद को आज़ाद करो। अपने वोट की ताक़त को पहचानो। संगठित होना सीखो। एक बात और बता दूँ। इसके लिए संगठन बनाने की सख्त ज़रूरत है। संगठन बनाना ही नहीं उसे मज़बूत भी करना है। इसके लिए अभियान भी चलाना पड़ेगा। ज़मीन तैयार किए बिना कुछ नहीं होगा।

सत्ता में बैठे लोग इस बात की दलील ज़रूर देंगे कि आज़ादी के बाद से देश के मुसलमानों की हालात में सुधार हुआ है। इस बात से मुझे भी कोई इंकार नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि इस क्रौम का शोषण भी कुछ कम नहीं हुआ है। लेकिन

अपने हालात के लिए हम खुद ही ज़िम्मेदार हैं। और हालात बदलने के लिए हमें संगठित होकर आंदोलन करना पड़ेगा। ज़रूरत है एक आंधी की। लेकिन ये आंधी किस दिशा में बहेगी और किस मक़सद के लिए, ये भी हमें साफ़ मालूम होना चाहिये। मेरा

संगठित होने के साथ-साथ शिक्षित भी होना पड़ेगा। बिना तालीम के इंसान एक भेड़-बकरी जैसा ही होता है, जिसे चरवाहा मनमाफ़िक दिशा में हांक देता है। यही कारण है कि पिछले ६४ साल में मुसलमानों को ख़द्दरधारियों ने एक बकरी के झुंड के समान अपने स्वार्थ के लिए कभी इस खूँटे, तो कभी उस खूँटे बांधा है। और हम, बेतालीम बेअक़ल, बंधते चले गए। अगर हालात नहीं बदले तो आगे भी बंधते खूँटे से ही बंधते चले जाएंगे। लेकिन तालीम पाना अपने आप में लक्ष्य नहीं है। ये तो केवल एक माध्यम है। जिसके ज़रिये हम अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे। और वो है देश चलाने में साझेदारी का।

भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरपरस्त आरएसएस 20 फ़ीसदी मुसलमानों की मुख़ालफ़त करके आज तक अकेले दम पर इस मुल्क में सत्ता हासिल नहीं कर सकी। चूँकि इस देश में रहने वाले बाक़ी हिंदुओं को मुसलमानों की मुख़ालफ़त नागवार गुज़रती है। मेरा मानना है धर्मनिरपेक्ष लोगों को हमारी भागीदारी की मुहिम से कोई ग़ुरेज नहीं होगा।

यदि सत्ता में अपनी साझेदारी चाहिए तो हिंदुओं को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। मैं नेताओं की नहीं आम हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। जो क़ौम साझेदारी से अछूती रह गई है आप उसे अपनी तहरीक या मुहिम का हिस्सा बना सकते हैं। उसके साथ साझेदारी का नाता जोड़ सकते हैं। हिंदुस्तान में इंसान परस्त हिंदुओं की भी कोई कमी नहीं है। यदि आपका अख़लाक़ अच्छे हैं तो ये लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल सकते हैं। हम किसी के दुश्मन नहीं, बल्कि दोस्त हैं, और हमारे भाईचारे को सियासी मफ़ाद के लिए तोड़ने की कोशिश ना की जाये। लेकिन सत्ता की भागेदारी के लिए हमें अब चूकना नहीं है। अगर इस दिशा की तरफ़ क़दम बढ़े तो मुझे उम्मीद है कि मंजिल ज़रूर हमारे पास होगी। चूँकि दानिशवरों की मुसलमानों में कोई कमी नहीं। कमी है तो सिर्फ़ हमारे संगठित होने की।

मेरा मानना है कि जिस दिन सारे मुसलमानों ने अपना कोई अमीर चुन कर उसकी बात पर अमल करना शुरू कर दिया वो दिन यक़ीनन इंक़लाब का दिन होगा।

मेरी राय है कि दीन से जुड़े लोगों को मुसलमानों के भले के लिए खुद को राजनीत से अलग नहीं करना चाहिए। इससे बहुत बड़ा नुक़सान पूरी कौम को हो रहा है। मैं हर एक बुजुर्ग़ानेदीन, उलेमाओं, इमामों, और हर एक मुसलमान से गुज़ारिश करता हूँ कि वो इस तहरीक की कामयाबी के लिए खुदा से दुआ करें। अल्लाह ताआला हमें सत्ता में साझेदार बना कर लोगों का ख़िदमत गुज़ार बना दे। दोस्तो दुआ के साथ-साथ दवा भी करनी पड़ेगी। शायद तभी बरसों पुरानी बीमारी का इलाज हो सके।

आज हम यहाँ सियासत के सभी झूठे वादों को, सियासत से पैदा हुई सभी छोटी बड़ी मुश्किलात को और एक लम्बे समय से चली आ रही सड़ी गली सियासत को ख़तम करने का बीड़ा उठाने आये हैं.

मैं एक बात और साफ करना चाहूँगा, के जब आप इस क्रांति के झंडे के नीचे चलेंगे तो पूरे जोश के साथ चलेंगे. और हम सब एक परिवार हैं, और मशवरे से नतीजे निकाले जा सकते हैं. अब आप मेरे मशवरे पर आगे बढ़ना चाहोगे या वापस अपने साथ नाइंसाफी लिए जहाँ से आये थे वही जाना चाहोगे? लेकिन अगर तुम आज वापस चले गए तो इस जलसे की तरह हम भी एक दिन खाक को सुपुर्द हो जायेंगे. और मुसलमानों की चलती जद्दो जहद कागज़ की नाव की तरह हिंदुस्तान की सियासत की लहरों में बेमानी बहती रहेगी. या फिरसे ये जद्दो जहद हमें ऐसे ही शुरू करनी पड़ेगी जैसे की आज शुरू कर रहे हैं. और अगर आप को लगता है की ये मेहनत कभी रंग ही ना लाएगी, तो फिर मेरे पास आपसे कहने के लिए कुछ नहीं है.

और अगर आपको लगता है की मैं इस मुहीम का झंडा लेकर आगे चलने के काबिल नहीं, तो आप में से जो इस काबिल हो आए और इस झंडे को अपने मज़बूत इरादों के साथ थाम ले.

क्या तुमको डर है के तुम्हारे खिलाफ साज़िशें की जाएंगी, या तुमको बर्बाद कर दिया जायेगा, हाँ ऐसा होगा, मगर तब तक जब तक तुम इकट्ठा नहीं हो जाते. जम्हूरियत की ताकत को पहचानो और आगे बढ़ो, आपके मुस्तकबिल का सुन्हेरा हिंदुस्तान आपके सामने खड़ा है.

हम अक्सर ये बहाना करते हैं की कुछ नहीं हो सकता सिस्टम बहुत ख़राब हो गया है, कोई फायेदा ना होगा, या मेरे अकेले से क्या होगा. तो फिर कोन बदलेगा सिस्टम को, हमारे लिए हर एक चीज़ सिस्टम का हिस्सा है, मगर मैं खुद नहीं, ऐसा क्यों? हम चाहते हैं के जब हम रात को सोये तो फ़रिश्ते हमारा हक हमारे सामने लाके रख दें, और जब हम सुबह को जागें तो उठा के सीने से लगा लें. ऐसा क्यों? माना ये रास्ता लम्बा हो सकता है, मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है की हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे.

जो काफ़ला भी अजमो यकीं से निकलेगा ... जहाँ से चाहेगा रस्ता वहीं से निकलेगा

बहुत हुई वोटों की साझेदारी, अब करनी है सरकार में हिस्सेदारी

इस देश के मुसलमानों से मेरी विनती है कि बहकावे में न आएं। ये देश हमारा है। हम यहाँ किसी मजबूरी में नहीं बल्कि अपनी मर्ज़ी से हैं वरना हमारे पास रास्ता दूसरा भी था. हमें ही इसे बुलंदियों तक ले जाना है। गर्व के साथ अपने देश का झंडा ऊंचा रखिए और इसकी शान में कभी आंच न आने दीजिए। पूरी दुनिया और हमारे देश में ख़ूब तरक्की हो रही है। इस तरक्की का हिस्सा बनिये। एक अच्छे इंसान, एक अच्छे भारतीय, एक अच्छे मुसलमान बनिए।

हम आज यहाँ हिंदुस्तान में अपनी हिफाज़त और समाजी इन्साफ, और हिंदुस्तान के वसाएल में अपनी हिस्सेदारी लेने के लिए इखटटा हुए हैं, बरसों से की जा रही नाइंसाफी और अनदेखी की पूर्ती के लिए हमें आज हिंदुस्तान के सरमाये में अपना हिस्सा चाहिए, और ये सिफारिश रंगनाथ मिश्रा और सचर कमेटी की रिपोर्ट में भी की गयी थी.

हिंदुस्तान का हर मुस्लमान, चाहे वो किसी भी जात का हो, खस्ता और बदहाली की ज़िन्दगी जी रहा है. इसके लिए जनरल मुस्लिम रिज़र्वेशन ही कारगर है, अलबत्ता बेहद ज़रूरतमंद मुसलमानों के लिए, कौटा में कोटे का तरीका अपनाया जा सकता है. लेकिन मुसलमानों के किसी भी ग्रुप को रिज़र्वेशन से बाहर रखना, हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ सरासर नाइंसाफी होगी.

कुछ लोग कहते हैं की मुसलमानों को रिज़र्वेशन नहीं मिल सकता, जबकि आर्टिकल 15(4) में साफ लिखा है की सरकार को पूरी आज़ादी है की वो स्पेशल प्रोविज़न के तहत उनकी तरक्की के लिए प्रावधान बना सके जो समाजी और तालीमी एतबार से पिछड़ी कोमें हैं, अब बताओ क्या सारी मुस्लिम कोम समाजी और तालीमी एतबार से पिछड़ी नहीं है?

और आर्टिकल 16(4) में साफ लिखा है की सरकार को पूरी आज़ादी है की वो स्पेशल प्रोविज़न के तहत उस कोम की नोक़रियों के लिए रिज़र्वेशन का प्रावधान बना सके जो सरकारी नोक़रियों में ना के बराबर हैं, अब बताओ क्या मुस्लिम कोम सरकारी नोक़रियों में नदारद नहीं है?

इसके अलावा भी रास्ते हैं, सरकार सभी मुसलमानों को EBC यानि की अत्यंत पिछड़ा वर्ग में रख कर भी सभी को रिज़र्वेशन दे सकती है

और हम सरकार से ये भी अनुरोध करते हैं की सरकार जल्द से जल्द एक मज़बूत Anti Communal Violence Bill लागू करे जिससे हिंदुस्तान में रह रही अक्लियतें महफूज़ रह सकें.

और हम सरकार से ये भी अनुरोध करते हैं की सरकार जल्द से जल्द राष्ट्रीय और सभी राज्यों के अल्पसंख्यक आयोगों को पर्याप्त रूप से ताकतवर बनाये, जिससे हिंदुस्तान में रह रही अक्लियतों को समाजी नाइंसाफी और पक्षपात से रहत मिल सके.

हम अपनी इन मांगों का मेमोरेण्डम UPA Chairperson Smt. Sonia Gandhi, Prime Minister Manmohan Singh ji और Minority & Law Minister Salman Khurshid ji के सुपुर्द करेंगे. और इंतज़ार करेंगे इनके जवाब का की ये लोग हमारी हिफाज़त, इन्साफ और रिज़र्वेशन को लेकर कितने गंभीर हैं.

मैं ज्यादा वक़्त ना लेते हुए आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा और कहूँगा की ग़ोर करना.

और हम उन लोगों का इस्तक़बाल करेंगे जो लोग हमारी इस मुहीम में जुड़ना चाहेंगे या अपना मशवरा देना चाहें, और उन लोगों का इंतज़ार करेंगे जो अभी तक हमारी बात से दूर हैं या फिर अभी हमारी बात उनकी समझ में नहीं आई है,

अल्लाह सब को सोचने और समझने की तोफ़िक अता फरमाए. अमीन
अल्लाह हाफ़िज़